के विद्युतीकरण तथा 5000 पम्पसैटों के ऊर्जित करने की परिकल्पना की गई है। राज्यवार लक्ष्य और परिव्यय के बारे में निर्णय राज्य प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है। वर्ष 1988-89 के लिए निधियों के आवंटन तथा ग्राम विद्युतीकरण संबंधी लक्ष्यों को योजना आयोग में अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उड़ीसा राज्य के सभी गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा की जाती है बशर्ते वित्तीय संसाधन तथा अन्य निवेश उपलब्ध हों। मोटे तौर पर अनुमानों के अनुसार मयूरभंज जिले में शेष गांव का विद्युतीकरण करने के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित होगी।

विवरण

31-10-1987 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा राज्य के उन गांवों का जिले-वार विवरण जिनका विद्युतीकरण किया जाना है।

क्र0 सं0	जिला	गांव जिनका विद्युतीकरण किया जाना है
1.	बालासोर	1064
2.	बोलनगिर	905
3.	कटक	1389
4.	धेनकनाल	970
5.	गन्जन	1834
6.	कालाहण्डी	1579
7.	क्योंझर	697
8.	कोरापुट	3789
9.	मयूरभंज	1886
10.	फुलबनी	3390
11.	पुरी	1164
12.	सम्बलपुर	1332
13.	सुन्दरगढ़	482

गोबर गैस के उपयोग का प्रचार

2367. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में गोबर-गैस और जैवगैस (बायोगैस) के उपयोग संबंधी प्रचार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में 80 प्रतिशत खर्च करने और शौचालय संबंधी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ग) निर्माण-लागत को कम करने और गैस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या अनुसंधान कार्य किया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र तथा साथ ही साथ सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों को देहाती क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की संभाव्यता प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या पर निर्भर करती है।

(ख) सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र पहले से ही क्रमशः अधिक से अधिक 90 प्रतिशत तथा 70 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त करने उपयुक्त हैं। इन परियोजनाओं में जहां कहीं संभव हो, शौचालयों के निर्माण की लागत शामिल है। इसके अलावा पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए आर्थिक सहायता की निश्चित राशि दी जा रही है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों सहित सामान्य श्रेणी तथा छोटे एवं सीमान्त कृषकों के लिए छोटे आकार के संयंत्रों की लागत का क्रमशः 26 और 46 प्रतिशत के लगभग है।

(ग) अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबलित सीमेंट खंडों के बने डाइजेस्टर

वाले गणेश, प्रगति, दीनबन्धु और प्लांट नामक चार सस्ते माडलों का अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही विकास हो चुका है तथा इनका विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा बहु-पोशी डिजाइनों के विकास तथा गैस उत्पादन की कुशलता को बढ़ाने के लिए बम्बई, कालीकट, हैदराबाद, जोरहाट, पटना, पांडिचेरी, पुणे तथा सांगली में अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

Second Mine Expansion of Neyveli Lignite Corporation Limited

2368. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the spreaders project of the second mine expansion of Neyveli Lignite Corporation Limited has got delayed due to inexperienced handling by WMI (Cranes) Limited, Bombay and its foreign collaborator M/s. MANGHH of West Germany;

(b) whether the technical consultant of the project the Rheinbraun Consulting of West Germany has also made adverse observations against the said combine;

(c) if so, what are the details thereof and what is Government's reaction thereto;

(d) what are the other reasons for the delay; and

(e) what further steps are being taken to expedite the said project?

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

(e) The progress of work is as per the agreed time schedule.

हाथी समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

2369. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के संबंध में हाथी समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का किस हद तक क्रियान्वयन किया जा रहा है ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केवल जेनेरिक नामों वाली औषधियों ही बेची जायें, क्या व्यवस्था की गई है?

उद्योग मंत्रालय में रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औषधी नीति, 1978 की घोषणा हाथी समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप की गई थी। दिसम्बर, 1986 में घोषित नये उपायों का उद्देश्य अंतरालों को पाटना तथा 1978 की नीति के कार्यान्वयन में देखी गई अपर्याप्त ताओं को ठीक करना है।

(ख) 1986 के नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्तिम निर्णय दिए जाने तक जेनेरिक नामों को व्यापार नाम के दुगने आकार में प्रदर्शित किया जायेगा। आवश्यक औषधों की सूची में शामिल सभी औषधों के मामले में धीरे-धीरे जेनेरिक नामों को अपनाया जायेगा।

बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिए योजनाएं

2370. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बिहार में बिजली की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिए अपनी योजनाओं में कौन-कौन से